

संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक AI शासन के लिये नया मार्ग

स्रोत: डाउन टू अर्थ

संयुकत राष्ट्र महासभा (UNGA) ने कृत्रिम बुद्धमित्ता (AI) पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल और AI शासन पर वैश्विक संवाद की शुरुआत की है, जो AI के लाभों का उपयोग करने के साथ-साथ उसके जोखिमों को प्रबंधित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- AI शासन पर वैश्विक संवाद: यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक समावेशी मंच प्रदान करेगा, जहाँ राष्ट्र और हितधारक AI से जुड़ी उन
 महत्त्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा कर सकेंगे जिनका आज मानवता सामना कर रही है।
- Al पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल: यह Al अनुसंधान और नीतिनिरिमाण के बीच एक सेतु का कार्य करेगा। यह चुनौतियों का प्रवानमान लगाने और वैशविक Al विनियमन का मारगदरशन करने के लिये कठोर, सवतंतर और वैजञानिक आकलन उपलब्ध कराएगा।
- यह **वर्ष 2026 (जिनवा) और 2027 (न्यूयॉर्क)** में Al शासन पर वैश्विक संवाद में अपनी वार्<mark>षिक रि</mark>पीर्ट प्रस्तुत करेगा।

भारत में Al शासन

- वर्तमान में भारत में कोई समर्पित कृत्रिम बुद्धमित्ता (AI) कानून नहीं है। इसे मौजूदा ढाँचों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (साइबर अपराध, मध्यस्थ की जिम्मेदारी), डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डेटा गोपनीयता) और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) कानून (AI-जनित कार्यों से संबंधित)।
- नीति आयोग की राष्ट्रीय कृत्रमि बुद्धमित्ता रणनीति, 2018 स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षि, स्मार्ट सिटी और गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में Al अनुसंधान और विकास का मार्गदर्शन करती है, जबकि इसकी ज़िम्मेदार Al के सिद्धांत, 2021 नैतिक Al तैनाती पर केंद्रित हैं।
- भारत वैश्विक AI मंचों में सक्र्यि है। इसने ग्लोबल पार्टनरशि ऑन आर्टिफिशियिल इंटेलिजेंस (GPAI) समिट, 2023 की मेज़बानी की, AI एक्शन समिट 2025 में फ्राँस के साथ सह-अध्यक्षता की साथ ही AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेज़बानी करेगा।

और पढ़ें: सार्वजनकि सेवा वतिरण में AI, AI और भारत का कानूनी परदिशय

PDF Reference URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/un-charts-new-path-for-global-ai-governance